(ii) Rotation of staff at regular intervals in order to eliminate possibilities of officials developing vested interests;

(iii) Frequent physical verification of stocks of these depots.

(iv) Scanning of Files relating to Contracts being given for transportation of stocks.

(v) Identification of sensitive posts so that persons of proven honesty and ability are posted there.

(vi) Updating and computerisation of stock accounts to prevent manipulation of stock position in its district offices and Depots.

Government has allowed the Corporation to create 8 more Sub-Regional Offices to make the Corporation more effective and efficient.

**Reversal of Sugar Licensing Policy**

179. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have reversed its sugar licensing policy from de-licensing to free licensing;

(b) if so, the reasons thereof, particularly when there is a glut of sugar in the market; and

(c) number of mills set up since the reversal of the policy?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) No, Sir. The Government has, however, vide Press Note dated 10.1.1997 liberalised the licensing policy guidelines and the procedure for processing the applications received for setting up of new sugar mills and expansion of existing sugar mills.

(c) It generally takes 3 to 4 years to set up a new sugar mill.

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त गेहूं और चावल की मात्रा**

180. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1996 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) के गोदामों में गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी थी और उसके बाद उत्पादकों से प्राप्त गेहूं और चावल की मात्रा कितनी है; और

(ख) अप्रैल, 1996 से अक्तूबर, 1996 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को विक्रय किए गए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी थी और निगम द्वारा निर्यात के लिए खुले बाजार में और घरेलू खपत के लिए इन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा बेची गई?

**खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):** (क) दिनांक 1.4.96 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 147.10 लाख टन गेहूं और चावल की मात्रा होने का अनुमान था, जिसमें 111.45 लाख टन चावल और 35.65 लाख टन गेहूं शामिल है। अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए मिल मालिकों से लेवी के रूप में वसूल और एकत्र की गई गेहूं और चावल की मात्रा 183.11 लाख टन है जिसमें 101.29 लाख टन चावल और 81.82 लाख टन गेहूं शामिल है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए गेहूं और चावल की मात्रा 109.63 लाख टन (अनन्तिम) है जिसमें 64.61 लाख टन चावल और 45.02 लाख टन गेहूं शामिल है। खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए जारी की गई चावल और गेहूं की मात्रा क्रमशः 2.70 लाख टन और 16.83 लाख टन है।

**गेहूं आयात किये जाने के कारण**

181. **श्री ईश दत्त यादव:**
**श्री रामगोपाल यादव:**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी मात्रा में गेहूं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसा निर्णय किस तिथि को लिया गया और किस-किस देश से कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया;

(ग) आयातित गेहूं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और सरकार द्वारा आयातित गेहूं के आरक्षित भंडार को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) सरकार किन-किन माध्यमों से आयातित गेहूं जनता को किस दर पर उपलब्ध कराएगी और इसका बाजार भाव से उपलब्ध गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):** (क) और (ख) गेहूं के उत्पादन में गिरावट होने और इसके परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में गिरावट होने और घरेलू बाजार में गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 4.12.1996 को निदेश दिया कि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 2 मिलियन टन गेहूं का आयात किया जाए। राज्य व्यापार निगम ने अब तक 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए ठेका किया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

| देश का नाम | ठेकाबद्ध मात्रा (लाख टन में) |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 13.25 |
| कनाडा | 2.50 |
| अर्जेन्टीना | 1.00 |

(ग) अब तक ठेका किए गए गेहूं की कुल लागत और भाड़ा क़ीमत लगभग 290 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) है। यह निर्णय लिया गया है कि आयातित गेहूं की ढुलाई प्राथमिक रूप से उन तटवर्ती राज्यों में की जाए जहां खेप पहुंचेगी। भारतीय खाद्य निगम ने इन राज्यों में आयातित गेहूं के स्टाक का सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण करने के लिए व्यवस्था की है।

(घ) आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल के स्टाक में शामिल किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्टाक की पर्याप्तता पर निर्भर करते हुए आयातित गेहूं का उपयोग घरेलू उपयोग के लिए खुली बिक्री हेतु भी किया जा सकेगा। आयातित गेहूं का बिक्री मूल्य वही होगा जो विदेशी गेहूं का होगा तथा यह मूल्य उस योजना पर निर्भर करेगा जिसके अधीन इसे जारी किया गया है। आयातित गेहूं के स्टाक से देश में गेहूं की समूची उपलब्धता में वृद्धि होगी।

**Export of Sugar to ensure Clearance of arrears due to Cane Growers**

182. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government had decided to export sugar in order to ensure clearance of arrears due to cane growers;

(b) if so, the amount of sugar to be exported and the national stock position of sugar as it existed on the eve of the said decision; and

(c) how much sugar has since been exported and to which countries and at what rate?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) In view of the high level of production achieved during the sugar season 1994-95 and still higher production level during 1995-96 season, Government, has beginning August 1995, from time to time notified a quantity of 13.25 lakh tonnes of sugar for export in suitable instalments, under the provisions of Sugar Export Promotion Act, 1958, through the Notified Export Agencies viz. Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd. (ISGIEIC) & State Trading Corporation of India (STC). Against this, a quantity of about 11.00 lakh tonnes has been physically exported upto the month of January, 1997. Further, consequent upon De-Canalisation of export of sugar w.e.f. 15.1.1997, Government has placed a quantity of 2.5 lakh tonnes of free sale sugar out of 1996-97 season's production at the disposal of Agricultural and Processed Food Products Export Develop-